

श्रताधारण EXTRAORDINARY

भाग II—सन्द 3—-उपसन्द (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं∘ 36]

नई विल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 29, 1970/माघ 9, 1891

No. 36] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 29, 1970/MAGHA 9, 1891

इस भाग में भिन्न पूछ संख्या दी जाती है जिससे कि यह श्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 29th January 1970

S.O. 384.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Union Territories (Separation of Judicial and Executive Functions) Act, 1969 (19 of 1969), the Central Government hereby appoints the 1st day of March, 1970, as the date on which the said Act shall come into force in all areas—of the Union territory of Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands.

[No. F. 13/1/70-UTL-]

S.O. 385.—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution and in partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 1615, dated the 6th May, 1968, in so far as it relates to the exercise of powers and discharge of functions by the Administrator of the Union territory of Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands, the President hereby directs that the said Administrator shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers and discharge the functions under the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898), as amended by the Union Territories (Separation of Judicial and Executive Functions) Act, 1969 (19 of 1969), in relation to the Union territory of Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands, specified in column (1) of the Schedule hereto amended subject to the general condition that the Central Government may itself exercise all or any of those powers and discharge all or any of those functions, should it deem necessary so to do and subject to the special conditions, if any, specified in column (2) of the said Schedule.

2. This notification shall have effect from the 1st March, 1970-

Schedule showing the delegation of powers and functions under the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898), as amended by the Union Territories (Separation of Judicial and Executive Functions) Act, 1969 (19 of 1969) to the Administrator of the Union territory of Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands.

Powers and functions

Conditions subject to which exercisable

(1)

(2)

(i) All powers and functions of the State Government except those under section 14.

The powers to empower and Executive Magistrate under sub-section (1A) of section 164 shall be exercised only when the Judicial Magistrate is not available to record the statement or confession.

- (ii) Powers and functions of the Central Government under sub-section (3) of section 198B, in respect of persons employed in connection with the administration of the Union territory of Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands.
- (iii) Powers and functions of the appropriate Government under section 401, except in respect of—
 - (a) cases involving the sentence of death where such sentence has not been commuted;
 - (b) cases where the sentence is for an offence against any law relating to any of the matters coumerated in List I in the Seventh Schedule to the Constitution; and
 - (c) cases where the order referred to in subsection (4A) of section 401 passed under any law relating to any of the matters enumerated in List I in the Seventh Schedule to the Constitution.

[No. F. 2/1/70-UTL.]

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

भारत सरकार, गृह मंत्रालय

श्रधिसूचनाएं

नर्ष दिल्ली, 29 जनवरी 1970

का० आ० 384:—संघ राज्य क्षेत्र (न्यायिक ग्रीर कार्येपालक कृत्यों का पृथक्-करण) ग्रिधिनियम, 1969 (1969 का 19) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 1 मार्च, 1970 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त ग्रिधिनियम लक्कादीव, मिनिकोय ग्रीर श्रमीनदीवी द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में प्रवृक्त हो जाएगा।

[सं० फ० 13/1/70—यू० टी० एल]

कार आर 385:—संविधान के अनुष्छेव 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या कार आर 1615, तारीख 6 मई, 1968 को, वहां तक जहां तक कि उसका संबंध लक्कादीब, मिनिकोय और अमीनदीबी द्वीप समूह के संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासक द्वारा शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वेहन से हैं, आंशिक रूप से उपांतरित करते हुए, राष्ट्रपति एतद्बारा निदेश देते हैं कि उक्त प्रशासक, राष्ट्रपति के नियंद्यण के अधीन रहते हुए और आगे आदेश होने तक

लक्कादीव, मिनिकोय भौर श्रमीनदीवी द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में संघ राज्य क्षेत्र (न्यायिक और कार्यपालक कृत्यों का पृथक्करण) श्रिष्ठितियम, 1969 (1969 का 19) ब्रारा यथा संशोधित दण्ड प्रिक्रिया संहिता 1898 (1898 का 5) के अधीन उन शक्तियों का प्रयोग भौर उन कृत्यों का निर्वहन जो इससे उपावद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट हैं, इस साधारण शर्त के श्रव्यधीन कि यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझे तो वह स्वयं उन सभी शक्तियों का या उनमें से किसी का प्रयोग और उन सभी कृत्यों का या उनमें से किसी का निर्वहन कर सकेगी तथा उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट विशेष शर्तों, यदि कोई हों, के श्रव्यधीन करेगा।

2 यह ग्रधिसूचना 1 मार्च, 1970 से प्रभावी होगी।

लक्कावीय, मिनिकोय ग्रौर समीनबीबी द्वीपसमूह के संघ राज्यक्षेत्र (व्याधिक ग्रौर कार्यपालक कृत्यों का पृथवकरण) अधिनियम, 1969 (1969 का 19), द्वारा यथा संक्षोवित बन्ड प्रक्रिया सहिता, 1898 (1698 का 5), के अधीन की क्षितियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन बहितत करने वाली अनुसूची।

शक्तियां और श्रुत्य शर्त जिसके सधीन वह प्रयोक्तव्य है

(1)

- (i) धारा 14 के ग्रधीन की शक्तियों भीर छत्यों को छोड़कर, राज्य सरकार की सभी शक्तियों भीर कृत्य।
- धारा 164 की उपधारा (1क) के ब्राधीन कार्यं पालक मजिस्ट्रेट को सशक्त करने की शिक्षत का प्रयोग केवल तभी किया जाएगा जब कथन या संस्वीशृति को अभिलिखित करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट मौजूद न हो ।
- (ii) धारा 198 की उपधारा (3) के स्रधीन, लवकादीय मिनिकीय और स्ममीनदीकी हीप समूह के संघ राज्यक्षत्र के प्रशासन के मंबंध में नियोजित व्यक्तियों की बाहत, केन्द्रीय सरकार की शक्तियां और कृत्य ।
- (iii) निम्नलिप्तित के संबंध में छोड़कर, धारा 401 के अधीग समुन्तित सरकार की शक्तियां और कृत्य:
 - (क) यह मामले जिनमें मृत्यु दंशदेश श्रन्त-वंतित हो किन्तु जिनमें ऐसा दंशदेश लधु-कृत नहीं किया गया हो ;
 - (ख) वह मामले जिनमें दण्डादेण संविधान की सन्तम प्रापुची की सूची 1 में प्रगणित थिषयों में से किसी के संबंध में किसी विधि के बिरुद्ध ग्रयराध के लिए हो, तथा

(1)

(2)

(ग) वह मामले जिनमें धारा 401 की उप-धारा (4क) में निर्दिष्ट घादेश, संविधान की सप्तम प्रनृसूची की सूची 1 में प्रगणित विषयों में से किसी के संबंध में किसी विधि के प्रधीन पारित किया गया हो ।

> [सं० एफ० 2/6/69-यू० टी० एल] के० ग्रारण प्रभु, संयुक्त मंत्रिक, भारत सरकार ।